नईदुनिया

एक नजर इधर भी

मुख्य सचिव अनुराग जैन से मंत्रालय में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य संजय वर्मा ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा एवं एसीएस सामान्य प्रशासन संजय शुक्ला भी उपस्थित थे।

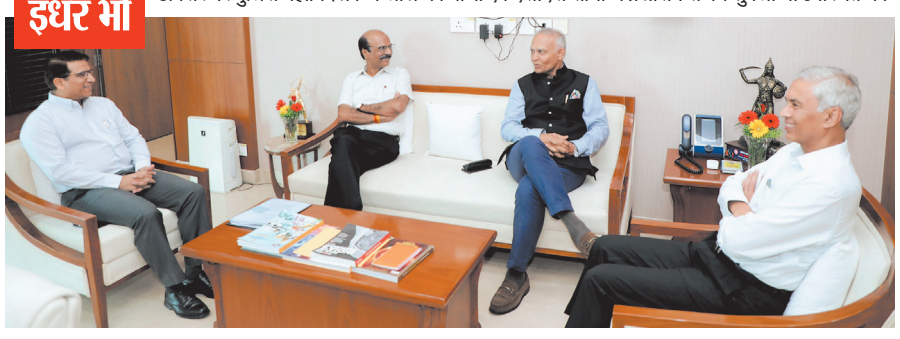

डीपीसी पूरीः राज्य पुलिस सेवा के नौ अफसर बनेंगे आईपीएस, दो पर सस्पेंस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश के राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 9 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक पूरी हो गई है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य संजय वर्मा की मौजूदगी में हुई इस बैठक में चयनित नामों को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया में वर्ष 1997 और 1998 बैच के अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया। कुल 27 अधिकारियों के नामों पर चर्चा हुई, जिनमें से 9 अधिकारियों का चयन आईपीएस पदोन्नति के लिए किया गया है।

चर्चा में शामिल प्रमुख नामों में 1997 बैच के सीताराम ससत्या और अमृत मीणा तथा 1998 बैच के निमिषा पांडेय, राजेश मिश्रा, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा सोनी, सुमन गुर्जर, संदीप मिश्रा, सब्यसाची सर्राफ, समर वर्मा और सत्येंद्र सिंह तोमर शामिल रहे।

जानकारी के अनुसार सीताराम ससत्या और अमृत मीणा के नाम चयन सूची से बाहर हो सकते हैं। वहीं राजेश मिश्रा और संदीप मिश्रा की पदोन्नति विभागीय जांच के कारण अटक सकती है। बताया जा रहा है कि इन दोनों अधिकारियों के लिफाफे फिलहाल बंद रखे गए हैं, जिससे उनका निर्णय अंतिम रूप से लंबित है।

मोहर्रम जुलूस में वैन को लटकाकर किया विस्फोट

बिना अनुमति विस्फोट करने के मामले में आयोजक, क्रेन मालिक सहित चार पर प्रकरण दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैनः उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान वैन में किए गए विस्फोट का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह घटना 23 जून की रात अड़ान मोहल्ले से निकले जुलूस की बताई जा रही है। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे।

जानकारी के अनुसार, एक वैन को क्रेन की सहायता से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। वैन की छत पर दो युवक लाल झंडे लहराते दिखाई दिए। इसके बाद वैन में विस्फोट किया गया। वैन पर 'ले फिर आ गए' लिखा हुआ था। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद इस पर आपत्ति भी जताई गई।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में विस्फोट के अलावा विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन भी दिखाई दे रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर संत स्वामी शिवानंद गिरि ने सामाजिक माध्यम पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसकी जांच की मांग

की। वहीं, हिंदू जागरण मंच के रितेश माहेश्वरी ने कहा कि जुलूस के दौरान इस प्रकार की गतिविधि की अनुमति दिए जाने को लेकर जिला प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करनदीप सिंह ने बताया कि मामले में आयोजक शोएब खान, वैन पर झंडा लहराने वाले तालीम खान और जाहिद खान तथा क्रेन मालिक गोपाल माली के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 285, 286 और 287 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार जुलूस की अनुमति दी गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार के विस्फोटक के उपयोग की अनुमति नहीं थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दीपावली में उपयोग होने वाले रॉकेटों को एक साथ चलाने से वैन के भीतर दबाव बना, जिससे कांच टूटने पर विस्फोट जैसा दृश्य दिखाई दिया।

राहुल ने खेद जताया है तो याचिका निरस्त की जाए : कार्तिकेय सिंह

राहुल गांधी ने कहा- भ्रमवश लिया था कार्तिकेय का नाम, हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुरः मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच चल रहे मानहानि प्रकरण की सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मामले में आदेश आज अथवा सोमवार तक आने की संभावना जताई जा रही है।

उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। सुनवाई के दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से कहा गया कि यदि राहुल गांधी ने भ्रमवश उनका नाम लिया था और इस पर खेद भी व्यक्त कर दिया है, तो अब उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। इसके आधार पर मानहानि की कार्रवाई तथा राहुल गांधी की याचिका का निराकरण किए जाने की मांग की गई।

कार्तिकेय सिंह चौहान के अधिवक्ता संकल्प कोचर ने न्यायालय में कहा कि राहुल गांधी ने अपने लिखित उत्तर में स्वीकार किया है कि उन्होंने भूलवश पनामा पेपर्स प्रकरण में कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका बयान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अथवा कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था और इस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है।

यह मामला वर्ष 2018 के झाबुआ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के एक भाषण से जुड़ा है। चुनावी सभा में उन्होंने पनामा पेपर्स प्रकरण का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। बाद में उच्च न्यायालय में दायर आवेदन में राहुल गांधी ने कहा कि भाषण के दौरान भ्रम की स्थिति में कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम आ गया था, जबकि उनका आशय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक का नाम लेने का था। कार्तिकेय सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि इस बयान से उनकी प्रतिष्ठा और छवि को क्षति पहुंची।

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र प्रहरियों को किया नमन

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरूद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि 25 जून, 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के दिन ही 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणामस्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव समर्पित होकर देश की सेवा का संकल्प लेने का प्रदेशवासियों से आव्हान किया।

ट्रक से टकराई कार, चार की मौत

मंदसौरः मंदसौर में दिल्ली-मुंबई आठ लेन एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

अटल आवास से नौकरी तकः प्रमिला तिवारी का ठगी नेटवर्क उजागर

भोपाल से रीवा तक फैला फर्जीवाड़ा, नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अटल आवास योजना के तहत फ्लैट दिलाने के नाम पर शुरू हुआ धोखाधड़ी का मामला अब बड़े नेटवर्क का रूप ले चुका है। गिरफ्तार प्रमिला तिवारी और उसके गिरोह ने भोपाल, रीवा, जबलपुर, बैतूल और सतना के युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगे।

जांच में सामने आया कि गिरोह वन विभाग, रेलवे, एसबीआई, पीडब्ल्यूडी, एम्स और नगर निगम जैसे संस्थानों के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करता था। भोपाल के नवीन सौंधिया को वन विभाग का फर्जी पत्र देकर उन्हें आईएफएस अधिकारी बताया गया, जबकि राजीव विश्वकर्मा को

एसबीआई में नौकरी का झांसा दिया गया।

रीवा के राकेश दुबे की पुत्री से पांच लाख रुपये लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री के हस्ताक्षरयुक्त फर्जी पत्र दिया गया। इसी तरह अन्य जिलों के युवाओं को भी नकली दस्तावेज देकर ठगा गया।

गिरोह सरकारी दफ्तरों के बाहर मुलाकात कर भरोसा जीतता था। कुछ लोगों को अस्थायी काम भी कराया जाता था ताकि प्रक्रिया असली लगे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास युवाओं की शैक्षणिक जानकारी और मोबाइल नंबर पहले से मौजूद थे।

टीटी नगर थाना पुलिस ने प्रमिला तिवारी को 18 जून को गिरफ्तार किया। यह मामला अटल आवास योजना में फ्लैट दिलाने के नाम पर 1.80 लाख रुपये की ठगी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता प्रतीक सोनी को दिए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए।पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।

निर्माण कार्य शुरू करने से 30 दिन पहले श्रम विभाग को सूचना देना अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी भवन या निर्माण कार्य को शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक को सूचना देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के तहत निर्माण स्थल का विवरण, कर्मचारियों की संख्या, लोकेशन और सुरक्षा संबंधी जानकारी 'श्रम सेवा पोर्टल' मोबाइल ऐप अथवा एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से भी सूचना दी जा सकेगी।

श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यकतानुसार सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती अनिवार्य रहेगी। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी भी की जाएगी। विभाग के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निर्धारित सूचना नहीं देता है, तो उसे तीन महीने तक की जेल, दो हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों दंड का सामना करना पड़ सकता है। सभी सरकारी निर्माण विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले श्रम विभाग को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को अधिक अवसर दें विश्वविद्यालय : राज्यपाल पटेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत2047 के संकल्प को साकार करने के लिए विश्वविद्यालयों को युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण की भावना, कौशल और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करना उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

राज्यपाल गुरुवार को लोकभवन में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 102वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के संचालन, समन्वय और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गई।

उन्होंने विश्वविद्यालयों को प्रत्येक दो वर्ष में पूर्व विद्यार्थियों का प्लेसमेंट सम्मेलन आयोजित

करने की सलाह देते हुए कहा कि इससे वर्तमान विद्यार्थियों को प्रेरणा और करियर मार्गदर्शन मिलेगा। राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालयों में योग को नियमित गतिविधि के रूप में शामिल करने और इसकी शुरुआत छात्रावासों से करने का सुझाव दिया। श्री पटेल ने रोजगारोन्मुखी प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को गरीब और वंचित परिवारों की आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कृषि से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए भी प्रमाणन व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया। साथ ही विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों को गांवों से जोड़ने, ग्रामीण विकास गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पीएम-जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना जैसे अभियानों में सहयोग देने का आह्वान किया। उनका कहना था कि गांवों के भ्रमण से विद्यार्थियों में वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन गंभीर अनियमितता है। उन्होंने कुलपतियों से सभी वित्तीय निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन पोर्टल के माध्यम से ई-प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ना स्वैच्छिक है, लेकिन प्रवेश संबंधी जानकारी आयोग के पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होना अनिवार्य रहेगा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयुक्त उच्च शिक्षा प्रबल सिपाहा सहित शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

आदिवासी मुद्दों के लिए जल-जंगल-जमीन पर कांग्रेस की विशेष समिति गठित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के अधिकारों और जल, जंगल तथा जमीन से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस ने विशेष उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अभा कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने समिति के गठन की घोषणा की। समिति प्रदेश में आदिवासी समुदाय से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का अध्ययन कर पार्टी की रणनीति तैयार करेगी।

समिति में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह (राहुल भैया) तथा आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि समिति आदिवासी समाज के संवैधानिक और पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने का कार्य करेगी।

समिति का प्रमुख फोकस जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा आदिवासी क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों का अध्ययन रहेगा। इसके अलावा समिति विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से संवाद करेगी और उनकी समस्याओं के आधार पर संगठन की भावी रणनीति तैयार करेगी।

कांग्रेस का मानना है कि आदिवासी क्षेत्रों में जमीन, वन अधिकार और आजीविका से जुड़े मुद्दे लंबे समय से प्रमुख रहे हैं। कांग्रेस आगामी समय में आदिवासी वर्ग के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाने और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

• हम भी तो हैं इंतजार में...

तबादलों की प्रक्रिया शुरू होते ही कई साहबों के चेहरे पर नई चमक दिखाई देने लगी थी। कप्तान की कुर्सी से उठकर डीआईजी की कुर्सी तक पहुंचने के सपने भी सजने लगे थे। मगर इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ साहब हर सुबह नई सूची आने की उम्मीद में दिन की शुरुआत करते हैं और शाम तक उम्मीद अगले दिन पर टाल देते हैं। फिलहाल कई जिलों में कप्तानी भी चल रही है और प्रमोशन की आस भी बनी हुई है। हालात कुछ ऐसे हैं कि कुर्सी भी अपनी है और नजर दूसरी कुर्सी पर भी टिकी हुई है।

• मुखिया कौन बनेगा?

इन दिनों पुलिस महकमे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विभाग की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी। दावेदारों के नामों पर चर्चा खूब हो रही है और समर्थकों ने अपने-अपने हिसाब से गणित भी बैठा रखा है। लेकिन मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जानने वाले मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहते हैं कि अंतिम नाम वही होगा जिसकी चर्चा सबसे कम हो रही होगी। इसलिए फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है और इंतजार का मौसम जारी है।

• काश, ऐसी गंभीरता और मामलों में भी होती...

राजधानी में छह वर्षीय बच्चे की गुमशुदगी पर पुलिस ने जिस तेजी से कार्रवाई की और बच्चे को सुरक्षित ढूंढ़ निकाला, उसकी खूब सराहना हुई। लेकिन इसी के साथ उन परिवारों की उम्मीदें भी जाग गई हैं जिनके बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट महीनों से फाइलों में घूम रही है। लोग पूछ रहे हैं कि साहब, अगर हर मामले में यही फुर्ती दिखाई जाए तो न जाने कितने घरों की बुझती उम्मीदें फिर से रोशन हो सकती हैं। आखिर हर परिवार के लिए उसका बच्चा सबसे बड़ा वीआईपी ही होता है।

• आगे का रास्ता कठिन है, साहब...

अपनी साफ-सुथरी छवि और कामकाज के दम पर बड़े जिले की कप्तानी का सपना देख रहे एक साहब इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। अपराधियों पर कार्रवाई हो या अपराधों का खुलासा, हर मोर्चे पर सबसे आगे रहने की कोशिश है। चर्चा है कि साहब अपनी कार्यशैली से बड़े लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। हालांकि जानकार यह भी कहते हैं कि मंजिल जितनी बड़ी है, रास्ता भी उतना ही कठिन है। इसलिए मेहनत के साथ धैर्य की भी जरूरत पड़ेगी।

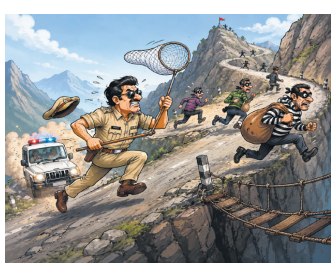

• काम ऐसा कि सभी को प्रेरणा मिली...

भोपाल से ग्वालियर के रास्ते में पड़ने वाले एक जिले के कप्तान साहब इन दिनों अच्छी वजह से चर्चा में हैं। मानव तस्करी से जुड़े एक गंभीर मामले में जिस संवेदनशीलता और तत्परता के साथ पूरी टीम ने काम किया, उसने लोगों का ध्यान खींचा है। अपराध का खुलासा तो हुआ ही, पीड़ितों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की कोशिशों ने भी सराहना बटोरी है। महकमे में चर्चा है कि अगर हर जिले में ऐसी ही संवेदनशीलता दिखाई जाए तो पुलिस की छवि अपने आप बेहतर हो जाएगी।

• हमारी भी सुनो, सरकार...

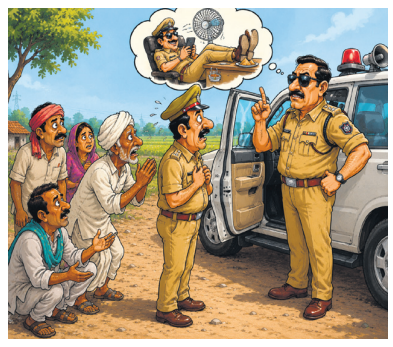

महाकौशल क्षेत्र में कुछ ग्रामीण अपनी समस्या लेकर एक दरोगा जी के पास पहुंचे। मगर साहब उस समय वीवीआईपी ड्यूटी में इतने व्यस्त थे कि फरियाद सुनने का समय नहीं निकाल पाए और ग्रामीणों को बाद में आने की सलाह दे दी। मायूस ग्रामीण लौट ही रहे थे कि रास्ते में बड़े साहब की नजर उन पर पड़ गई। गाड़ी रुकी, फरियाद सुनी गई, समस्या का समाधान हुआ और दरोगा जी को भी समझाइश मिल गई। अब इलाके में चर्चा है कि कभी-कभी जनता की समस्या भी वीवीआईपी ड्यूटी जितनी महत्वपूर्ण हो सकती है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com